इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2607

15 दिसम्बर, 2011 को उत्तर के लिए

लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन

2607 श्री किशोर कुमार मोहन्ती:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन' योजना विगत तीन वर्षों से पर्याप्त राजकोषीय आवंटन के बिना अभी भी धीमी गति से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना जिसे विशिष्ट रूप से इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और आयातित कुकिंग कोयले पर निर्भरता घटाने के लिए आरंभ किया गया था, के निश्चेष्ट कार्यकरण के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने इस कार्यक्रम के इष्टतम संचालन और चालू वर्ष में अनुमानित राजकोषीय आवंटन के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): इस्पात उद्योग पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने 118.00 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संवर्धन नाम की एक नई योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने तीन विस्तृत क्षेत्रों में आर एंड डी पर कार्यवाही करने का निर्णय किया है, वे हैं – (i) भारतीय लौह अयस्क चूरे और नॉन-कोकिंग कोल का उपयोग करते हुए नवाचारी/नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करना (ii) इन्डक्शन फर्नेस रूट के जरिए उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करना (iii) लौह अयस्क, कोल आदि कच्ची सामग्रियां और समिश्रण (उदाहरणतया पिलेटाईजेशन) का बेनीफिकेशन। उपरोक्त आर एंड डी स्कीम का अनुमोदन वास्तविक रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.1.2009 को इस निर्देश के साथ किया गया कि यह वर्तमान वर्ष की अंतिम अवधि होने के कारण इस योजना को अगले वित्त वर्ष 2009-10 में संचालित किया जा सकता है।

इस योजना के तहत अभी तक विशेषज्ञों के समूह द्वारा अनुशंसित 8 आर एंड डी परियोजनाओं का परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 143.87 करोड़ रूपये है जिसमें सरकारी अनुदान 96.23 करोड़ रूपये का है। अभी तक 39.02 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्ष 2011-12 के लिए राजकोषीय आबंटन 29.0 करोड़ रूपये है जिसमें से 7.84 करोड़ रूपये 4 आर एंड डी परियोजनाओं के लिए जारी किए जा चुके हैं।

****